गैस सिलेंडर और हरी-हरी घास

अपनी बीवी को पार्षद बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे एक सज्जन का पूरा जोर गैस सिलेंडरों पर है। चीख-चीख कर कहते हैं कि अब तक एक खास पार्षद ने सिलेंडर ब्लैक करके पैसे कमाये हैं। वे कहते हैं कि वैसे वे भी दूध के धुले नहीं हैं, पर उन्होंने कभी भी सिलेंडर ब्लैक नहीं किये। उनकी कमाई का 'जरिया' और ही रहा है। उनका कहना है कि जनता ने अगर उनकी धरम पत्नी को पार्षद बनाया तो उनका पहला काम होगा कि लोगों के बीच सिलेंडर बंटवायें। वहीं 'धरम पत्नी' का कहना है कि जब तक चुनाव परिणाम आदि आयेंगे, बरसात शुरू हो जायेगी और वे जनता की भलाई के लिए पार्कों में हरी-हरी घास लगवायेंगी।

पढ़े-लिखों को कौन पूछे?

चुनाव लड़ रही एक मोहतरमा सारा जोर पढ़ाई-लिखाई पर ही दे रही हैं। कह रही हैं कि नेहरू जी ने कहा था कि पढ़ाई-लिखाई से ही विकास हो सकता है। इसी से उन्हें शिक्षा मिली है कि वे पढ़ाई-लिखाई पर ही जोर दें। चुनाव जीतने पर वे पढ़ाई-लिखाई को ही बढ़ावा देना चाहेंगी। मोहतरमा खुद भी पढ़ी-लिखी लगती हैं। पर जहां झुग्गियों में अवैध शराब बेचने वाली महिलायें चुनाव मैदान में खड़ी हों, पढ़े-लिखों को कौन पूछता है।

क्या होगा भाजपा का?

झारखंड में साबित हो गया कि भाजपा में अब आडवाणी की नहीं चल रही। आडवाणी का गुट अब प्रभाहीन हो गया। गडकरी के नेतृत्व में भाजपा ने यह निर्णय लेकर कि वह वहां सरकार बनायेगी, आत्मघात का रास्ता अपना लिया है। अब ले-दे कर कांग्रेस के बाद भाजपा ही एक ऐसी पार्टी रह गई है जो तथाकथित राष्ट्रीय कही जा सकती है। पर गडकरी इसका बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। ऐसे भी भाजपा बहुत पहले से ही अपने पूर्णतया पतन के मार्ग पर चल पड़ी थी, पर संभवत: गडकरी को इसीलिए लाया गया है कि वे जितनी जल्दी हो सके, इसका अंतिम संस्कार कर दें।

कान पकड़ कर माफ़ी मांगें

गडकरी ने लालू और मुलायम को सोनिया के दरबार का कुत्ता कह दिया। इस पर दोनों यादव नेताओं का भड़कना स्वाभाविक ही था। वैसे गडकरी साहब ने अपने इस वक्तव्य पर माफ़ी मांग ली है। पर मुलायम इस मामले को अदालत में ले जाना चाहते हैं। वहीं, लालू इसी बात से संतुष्ट हो जायेंगे कि गडकरी कान पकड़ कर माफ़ी मांगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे उनके खिलाफ़ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना है कि गडकरी साहब कान पकड़ कर माफ़ी मांगते हैं या नहीं। अगर वे कान पकड़ लेते हैं तो इससे भारी उनकी बेइज्जती हो नहीं सकती। एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष भला कान पकड़े। दूसरी तरफ, मुलायम उन्हें सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं हैं। इससे गडकरी सांसत में हैं। पर भाजपा का एक खेमा इससे मन ही मन खुश भी है। गडकरी इस प्रकरण में 'संघम् शरणम गच्छामि' के बारे में सोच रहे हैं। पर संघ नेतृत्व की समझ में भी यह नहीं आ रहा है कि वह गडकरी की मदद कैसे करे। अगर गडकरी ने कान पकड़ लिया तो यह सिर्फ़ उनकी ही नहीं, पूरी भाजपा के लिए डूब मरने की बात होगी।

नीतीश का रंगीन चश्मा

इस वर्ष अक्टूबर में बिहार में चुनाव है। नीतीश भाजपा के सहयोग से फिर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बिहार में विकास की आंधी ही नहीं, तूफान ला दिया है। पैंतालिस हज़ार अपराधियों को जेल के सींखचों के पीछे भेजा है। वे विश्वास यात्रा, विकास यात्रा, तरह-तरह की यात्रायें कर रहे हैं और भाजपा की तर्ज पर रथयात्राओं की योजनायें भी बनाई है। लेकिन उन्होंने राज्य में कैसा विकास किया है, इसका पता इसी से चलता है कि उनके शासन काल में बिहार में कहीं एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी। पर कहते हैं कि वे राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां तक अपराधियों को जेल भेज कर राज्य का विकास कराने की बात है तो बेशक उन्होंने छोटे अपराधियों को जेल भेजा हो, पर माफ़िया को जेल नहीं भेज सकते। माफ़िया की पीठ पर तो वे खुद सवार हैं। विकास का पता इससे भी चलता है कि क्या पढ़े-लिखे, क्या अनपढ़ अपना पेट भरने के लिए रोज ही राज्य से पलायन कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में जा कर वहां गालियां सुन व मार खा कर मेहनत-मशक्कत कर रहे हैं। रंगीन चश्मा लगाने वाले नीतीश को यह ब्लैक एंड व्हाइट आखिर कैसे दिखेगा?

अब इंगलैंड में दिखायेंगे जलवा

ललित मोदी को अब सोने की खानें इंगलैंड में दिखाई पड़ रही हैं। आईपीएल में अपना खेल खत्म होते देख और मुकदमेबाजियों में फंस जाने के कारण ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अब भारत में लूटने-खसोटने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने इंगलैंड के काऊंटी क्लबों के मालिकों-मैनेजरों को समझाया है कि वहां भी आईपीएल जैसा तमाशा शुरू करो, पैसा बरसेगा। सुनने में आ रहा है कि काऊंटी क्लबों को मोदी की बात भा गई है। अब उन्हें इंगलैंड से 'धंधा' जमाने के लिए बुलावा आ रहा है। विदेशी खिलाड़ियों की खरीद-बिक्री का प्रबंध करने में माहिर मोदी का कहना है कि उनकी योजना में इंगलैंड का बोर्ड अगर रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा तो वे खिलाड़ियों को सीधे खरीद लेंगे। देखना है मोदी इंगलैंड कब तक जाते हैं और वहां क्या जलवे दिखाते हैं।

गपशप

क्या सरकार अपनी नाक बचा सकेगी?

दिल्ली को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चमकाया जा रहा है। चमकाने का यह काम तो पहले ऐसी गति से किया गया कि लगा कि खेल खत्म हो जाने पर भी यह काम खत्म हो पायेगा या नहीं।

उसी दौरान जो खेलमंत्री थे, प्राय: ही अख़बारों में अपना विचार प्रकट करते थे कि भारत जैसे ग़रीब देश पर खेल की अय्याशी का बोझ नहीं डालना चाहिए। यह बात उन्होंने इतनी ज्यादा कही कि खेल विभाग से उनकी छुट्टी कर दी गई। उसके बाद जो खेल मंत्री बनाये गये, उन्होंने सरकार की हां में हां मिलाना जारी रखा है। सरकार राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को देश के लिए गौरव की बात बता रही है। पर काम जो है वह पहले की गति से भी मंद पड़ गया है। मज़दूर तो दिन-रात काम कर रहे हैं, पर सिर्फ उनके काम करने से कुछ होता नहीं। सवाल है, सरकार क्या कर रही है और आगे क्या करेगी? कहीं ऐसा न हो कि समय पर काम पूरा ही न हो और सरकार की नाक न कट जाये।

बारूद के ढेर पर

बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बारूद की ढेर पर बैठे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि यहां आर्थिक क्षेत्र में कोई संभावना नहीं रह गई है। बिहार में गत ढाई दशकों से कोई इंडस्ट्री लगी ही नहीं। झारखंड जब से बना है, वहां लुटेरों का राज कायम है। एक लुटेरा जाता है और दूसरा लुटेरा आता है। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है। भाजपा सरकार ने इस बात की पूरी छूट दे रखी है कि जिसे भी इस राज्य को लूटना है, लूट ले और इस लूट में थोड़ा हिस्सा उसे भी दे दे। ऐसी हालत में विद्रोही तो पैदा होने ही थे जो पैदा हो चुके हैं और सरकार को रोज ही उसकी हैसियत बता रहे हैं। ऐसे में सरकार बेकार ही सीआरपीएफ जवानों को मरवा रही है। सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि वह विद्रोहियों पर काबू पा सके। अत: रमण सिंह को चाहिए कि जैसे बिहार और झारखंड में नीतीश और शिबू सोरेन ने विद्रोहियों से समझौता कर लिया है, उसी तरह वे भी समझौता कर लें। बेचारे सिपाही तो मरने से बचेंगे।

कहां गये उमा भारती और गोविंदाचार्य?

संन्यासिन उमा भारती बहुत दिनों से ख़बरों की दुनिया से दूर हैं। पहले ऐसी चर्चा चली थी कि उनकी भाजपा में वापसी हो रही है। इसी के साथ ही उनके 'प्रेमी' चिंतक गोविंदाचार्य की चर्चा भी चली थी कि आरएसएस अब उन्हें वनवास से बुलाने जा रहा है। पर उनकी भी कोई चर्चा बाद में मीडिया में नहीं आई।

पता नहीं, वे कहां चले गये? दरअसल, उमा भारती की 'घरवापसी' तभी हो सकती थी जब आडवाणी ऐसा चाहते। आडवाणी की अच्छी-खासी पैर-पूजा उमा भारती ने कर रखी थी। पर क्या कहें अब आडवाणी की ही भाजपा में कुछ नहीं चल पा रही।

कांग्रेस की 'राबड़ी'

लोगों को यह पता नहीं था कि कांग्रेस में भी कोई 'राबड़ी' है। पर यह बताया पर्यावरण राज्य मंत्री जयराम रमेश ने। उन्होंने हाई कमांड सोनिया गांधी को ही कांग्रेस की राबड़ी देवी बता दिया। बताया तो कोई ग़लत नहीं किया। राजनीतिक ज्ञान के मामले में सोनिया गांधी राबड़ी देवी से कुछ ही ज्यादा हैं। और ज्यादा क्या, आंग्ल भाषा के विशेष प्रभाव से ऐसा आभास होता है। बहरहाल, जयराम को कड़ी चेतावनी दी गई है कि वे ऐसे 'रहस्योद्घाटन' न करें। इससे उनका कॅरियर प्रभावित हो सकता है। प्रभावित होता है तो हो, हालिया चीन यात्रा के दौरान भारतीय सरकार की कुछ मामलों पर उनके द्वारा खुली आलोचना करने पर जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा ही सौंप दिया जो स्वीकृत नहीं हुआ। बात यह है कि वे करें तो क्या करें, बेचारे को अख़बारों में कॉलम लिखते-लिखते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आदत पड़ गई है।

ग़रीबों के बीच बिल गेट्स

लगता है कि भारत के ग्रामीण ग़रीबों की लूट की कोई खास तगड़ी योजना दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कम्प्यूटर शाहंशाह बिल गेट्स बना रहे हैं, तभी तो 'युवराज' राहुल के साथ उनके चुनाव क्षेत्र में दिखाई पड़े। वहां उन्होंने गेट्स साहब के इंटरप्रेटर की भी भूमिका निभाई यानी हिंदी में अब कामचलाऊ नहीं रहे। उन्होंने गांवों की छात्राओं से गेट्स साहब का परिचय यह कह कर कराया कि तुम लोग जो कम्प्यूटर देखती हो, वह इन्हीं की देन है। बहुत ही सही 'ज्ञान' दिया 'युवराज' ने। इसके बाद गेट्स साहब बिहार के खगड़िया जिले के एक गांव का दौरा करने के क्रम में नाव पर बैठे दिखाई पड़े। अब दुनिया का सबसे धनी आदमी भारत के सबसे ग़रीब राज्यों यू.पी. और बिहार के गांवों के दौरे पर हो तो आदमी सोचने को मजबूर होता ही है। इनकी तो तस्वीर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के साथ छपनी चाहिए थी। पर न जाने ये किस तिकड़म में ग़रीब गांवों का दौरा कर रहे हैं।

पुलिस राज का बढ़ता ख़तरा

केंद्र सरकार ने माओवादियों के समर्थन में लेख आदि लिखने अथवा चर्चा करने वाले बुद्धिजीवियों को धमकाते हुए कहा है कि जाने अथवा अनजाने माओवादियों का समर्थन करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून के तहत किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है और उसे दस साल तक की सजा दी जा सकती है। सरकार की इस स्पष्ट घोषणा से ऐसा लगता है कि वह देश में माओवादियों के दमन के नाम पर पुलिस राज लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए वह आम जनता को सीधी धमकी देने की जुर्रत कर रही है। माओवादियों पर उसका तो कोई वश चलता नहीं, इसलिए वह खीझ में भर कर अब इस व्यवस्था से असंतोष प्रकट करने वालों को ही धमकाने लगी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सड़ांध मार रही व्यवस्था का उग्र विरोध सिर्फ माओवादी ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा विरोध दूसरे संगठनों के लोग भी कर रहे हैं जिन्हें माओवादियों की नीति और कार्यशैली से कोई लेना-देना नहीं है। पर सरकार की इस घोषणा से ऐसा लगता है कि वह किसी भी तरह के प्रतिरोध को सहन नहीं करना चाहती। लोग अभी इस बात को भूल नहीं पाये हैं कि सरकार ने माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. विनायक सेन को दो वर्षों तक जेल के सींखचों के पीछे रखा, लेकिन जब इसका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी विरोध बढ़ा तो मजबूर होकर उसे उन्हें छोड़ना पड़ा। पर दो वर्षों की मुफ़्त जेल तो डॉ. विनायक सेन को काटनी ही पड़ी। उनके जीवन के दो महत्त्वपूर्ण वर्ष क्या कोई सरकार उन्हें लौटा सकती है? अब सरकार ने जो ताज़ी धमकी दी है, इससे उन लोगों पर ख़तरे की आशंका बढ़ गई है जो वर्तमान शोषण और अन्याय भरी व्यवस्था का विरोध करते हैं। सरकार के लिए व्यवस्था विरोधी किसी भी लेख अथवा वक्तव्य से यह आशय निकाल लेना कठिन नहीं होगा कि यह माओवादियों के समर्थन में है। सरकार की इस धमकी से पुलिस का व्यवहार और भी बर्बर होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इससे किसी भी निरपराध पर व्यवस्था विरोधी व्यक्ति को माओवादियों का समर्थक होने के नाम पर गिरफ़्तार कर लिया जाना बहुत ही आसान हो जायेगा।

सरकार की इस धमकी से पुलिस का व्यवहार और भी बर्बर होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इससे किसी भी निरपराध पर व्यवस्था विरोधी व्यक्ति को माओवादियों का समर्थक होने के नाम पर गिरफ़्तार कर लिया जाना बहुत ही आसान हो जायेगा।

– प्रतिनिधि